TRAI CHAIRMAN, PD VAGHELA ON TRAI'S ROLE IN FUTURE

TRAI chairman is all for transparency and wants TRAI to be an enabler.

TRAI is getting its act together and wants to facilitate as an enabler rather than a disruptor. Recently the TRAI chairman spelt out some of his thoughts on TRAI.

"The way technology is changing and the way new players are coming, we must ensure a level playing field for all. We should not impose regulations or restrictions on the new players; less regulation is the best regulation," affirmed PD Vaghela.

PD VAGHELA

On OTT, Vaghela feels that OTT has no licensing fee and the same is the case with telecom. Under TRAI act, there is a mandate to regulate only those service providers to whom the government is giving license.

Vaghela feels broadcasting to be slightly difficult to regulate and the reasons as the stakeholders who are involved have very diverse interests and many times they are diametrically opposite to each other.

He cited an example of TRAI' New Tariff Order 3.0. There was a huge controversy and debates over that. Vaghela believes that TRAI has no business controlling the tariff.

He further added, "When we went for consultation, broadcasters, and to some extent DTH operators, wanted complete freedom and forbearance but when it comes to LCOs, and to some extent MSOs, they wanted regulation from TRAI. LCOs say that TRAI should completely regulate the pricing of the industry. For us it becomes very difficult to balance the interests of the stakeholders."

Vaghela is happy if the industry sits together and gives TRAI a roadmap on how everyone can go about with the problems. He feels that LCOs have problems and they have to be protected. There are a large number of LCOs whose subscription base is going down, their revenue is going down and this is a transition thing. This is a transition stage where all stakeholders have to take care of them. That is one concern TRAI has. ■

भविष्य में ट्राई की भूमिका पर ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला

ट्राई के अध्यक्ष सभी तरह की पारदर्शिता के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि ट्राई मजबूत बना रहे।

ट्राई अपने कार्य को एकसाथ कर रहा है और बाधित करने के बजाय एक समर्थक के रूप में सुविधा प्रदान कर रहा है। हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष ने ट्राई पर अपने कुछ विचार रखे।

'जिस तरह से तकनीक बदल रही है और जिस तरह से नये खिलाड़ी आ रहे हैं, हमें सभी के लिए एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करना चाहिए। हमें नये खिलाड़ियों पर नियम या प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, कम विनियमन सबसे अच्छा विनियमन है।' श्री पीडी वाघेला ने पुष्टि की। ओटीटी पर वाघेला को लगता है कि ओटीटी का कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है और दूरसंचार के मामले में भी ऐसा ही है। ट्राई अधिनियम के तहत केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने का शासनादेश है जिन्हें सरकार लाइसेंस दे रही है।

श्री वाघेला को लगता है कि प्रसारण को विनियमित करना थोड़ा मुश्किल है और इसमें शामिल हितधारकों के हित बहुत विविध होते हैं और कई बार वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं।

उन्होंने ट्राई के नये टैरिफ आदेश **3.0** का हावाला दिया। इस पर भारी विवाद और बहस हुई थी। वाघेला का मानना है कि ट्राई का टैरिफ को नियंत्रित करने का कोई काम नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि 'जब हम परामर्श के लिए प्रसारकों और कुछ हद तक डीटीएच ऑपरेटर, पूर्ण स्वतंत्रता और सहनशीलता चाहते थे, लेकिन जब एलसीओ और कुछ हद तक एमएसओ की बात आती है तो वे ट्राई से विनियमन चाहते थे। एलसीओ का कहना है कि ट्राई को पूरी तरह से चाहिए उद्योग के मूल्य निर्धारण को विनियमित करे। हमारे लिए हितधारकों के हितों को संतुलित करना बहुत कठिन हो जाता है।'

श्री वाघेला खुश हैं यदि उद्योग एकसाथ बैठता है और ट्राई को एक रोडमैप देता है कि हम समस्याओं के बारे में कैसे जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि एलसीओ को दिक्कते हैं और उनकी सुरक्षा करनी होगी। बड़ी संख्या में ऐसे एलसीओ हैं जिनका सब्सक्रीप्शन बेस नीचे जा रहा है, उनका राजस्व कम हो रहा है और यह बदलाव की बात है। यह एक संक्रमण का चरण है जहां हमें उनकी देखभाल करनी है। ट्राई की यही एक चिंता है। ■